

Daily Current Affairs

Date : 13 May, 2026



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	नवगठित 'थार इनक्व्यूबेशन एलायंस'
2.	'स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया' रिपोर्ट में राजस्थान
3.	मारवाड़ रत्न सम्मान - 2026
4.	'सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन' का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
5.	केंद्र सरकार की RCDF को ₹1500 करोड़ की सहायता हेतु सैद्धान्तिक सहमति
6.	लखवार परियोजना का राजस्थान के लिए महत्त्व
7.	'विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना' के क्रियान्वयन में राजस्थान शीर्ष पर
8.	प्री-एम्बेडेड मिनरल ब्लॉकों की नीलामी वाला देश का एकमात्र राज्य : राजस्थान
9.	राष्ट्रीय फ्लोरेस नाइटिंगेल पुरस्कार, 2026
10.	प्रशांत पिसे
11.	The Bench, the Bar, and the Bizarre और The Lawful and the Awful पुस्तक
12.	तीरंदाजी विश्व कप, 2026- चरण 2
13.	असम और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री
14.	'वन केस वन डेटा' और 'सु सहाय' पहल
15.	सेहत मिशन (SEHAT)
16.	जन सुरक्षा योजना (PMJJBY, PMSBY और APY) : 11 वर्ष पूर्ण
17.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 2026
18.	ICGS अचल
19.	फुल स्केल एक्टिवली कूल्ड लॉन्ग ड्यूरेशन स्ट्रैमजेट कंबिनेटर/इंजन

--:1:--



राजस्थान परिदृश्य



नवगठित 'थार इनक्यूबेशन एलायंस'



चर्चा में क्यों?

- राजस्थान में स्टार्टअप और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से हाल ही में, इंदौर में आयोजित क्षेत्रीय 'AIM सुमवाद' (मध्य भारत संस्करण) के दौरान 'थार इनक्यूबेशन एलायंस' का गठन किया गया।

सत्यमेव जयते

NITI Aayog

ATAL INNOVATION MISSION

थार इनक्यूबेशन एलायंस

नवाचार • सहयोग • उद्यमिता • समृद्धि

थार क्षेत्र में नवाचार से बदलते कल की ओर

--2--



मुख्य बिन्दु:

- **शुरुआत** : इस नवाचारी पहल की शुरुआत 'अटल इनोवेशन मिशन (AIM)' और 'नीति आयोग' द्वारा संयुक्त रूप से की गई है।
- 'थार इनक्यूबेशन एलायंस' के साथ ही 'मध्य प्रदेश इनक्यूबेशन कंसोर्टियम' की भी शुरुआत की गई है।
- नवगठित 'थार इनक्यूबेशन एलायंस' (TIA) राजस्थान में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगा।
- **उद्देश्य** : राजस्थान में नवाचार-आधारित विकास को बढ़ावा देना, स्थानीय समस्याओं के लिए तकनीकी समाधान खोजना और स्टार्टअप्स को मेंटरशिप व वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- **क्षेत्रीय सहयोग** : यह एलायंस राजस्थान के विभिन्न इनक्यूबेशन केंद्रों (Incubators) को एक साथ लाता है ताकि ज्ञान का आदान-प्रदान और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा मिले।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

अटल इनोवेशन मिशन (AIM)

- **शुरुआत** : वर्ष 2016 में।
- **सम्बद्ध विभाग** : नीति आयोग।
- अटल इनोवेशन मिशन, देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है।
- इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचारिता को बढ़ावा देने हेतु नए कार्यक्रमों और नीतियों को विकसित करना, विभिन्न हितधारकों के लिये मंच एवं सहयोग के अवसर प्रदान करना, लोगों के मध्य जागरूकता बढ़ाना और देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी हेतु एक 'अंब्रेला संरचना' (Umbrella Structure) विकसित करना है।

Daily Current Affairs

Date : 13 May, 2026



- AIM के मिशन निदेशक : दीपक बागला।

AIM के तहत संचालित प्रमुख पहलें:

- अटल टिकरिंग लैब।
- मॅटर इंडिया मिशन।
- अटल इनक्यूबेशन सेंटर।
- अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल बिज़नेस (ARISE)
- अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर।
- अटल न्यू इंडिया चैलेंज।

अटल टिकरिंग लैब (ATL)

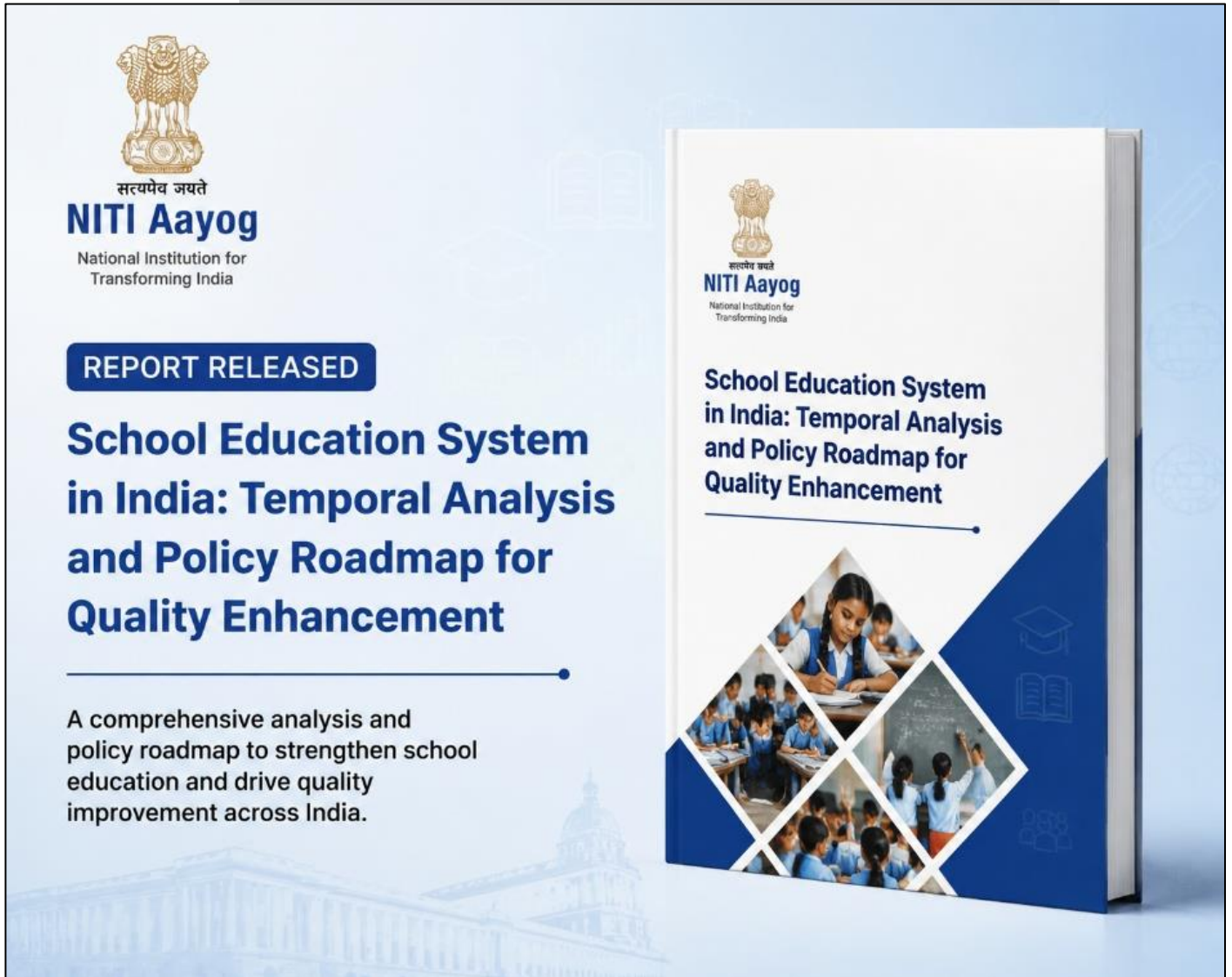
- नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के तहत अटल टिकरिंग लैब (ATL) की स्थापना कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए अपने अभिनव विचारों को साकार रूप देने के लिए की गई है।
- अटल टिकरिंग लैब के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए स्कूलों और विद्यार्थियों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के शोध के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन प्रौद्योगिकियों में 3D प्रिंटर, रोबोटिक्स, संवेदी प्रौद्योगिकी किट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आदि शामिल हैं।

--:4:--

'स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया' रिपोर्ट में राजस्थान

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, नीति आयोग द्वारा 'स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया - टेम्पोरल एनालिसिस एण्ड पॉलिसी रौडमैप फॉर क्वालिटी इन्हांसमेंट' रिपोर्ट जारी की गई।



The image shows the cover of a report released by NITI Aayog. The cover is white with a blue diagonal stripe at the bottom right. It features the NITI Aayog logo and the title 'School Education System in India: Temporal Analysis and Policy Roadmap for Quality Enhancement'. Below the title, there are three diamond-shaped images showing students in a classroom. The text on the left side of the image reads: 'REPORT RELEASED School Education System in India: Temporal Analysis and Policy Roadmap for Quality Enhancement. A comprehensive analysis and policy roadmap to strengthen school education and drive quality improvement across India.'

मुख्य बिन्दु:

- यह रिपोर्ट UDISE+, PARAKH, NAS और ASER के डेटा का इस्तेमाल करके 2014-15 से 2024-25 तक भारतीय विद्यालयी प्रणाली का व्यापक असेसमेंट प्रदान करती है।

- **UDISE+** : Unified District Information System for Education Plus (शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली)
- **PARAKH** : Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण)
- **NAS** : National Achievement Survey (राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण)
- **ASER** : Annual Status of Education Report (वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट)।

राजस्थान का प्रदर्शन :

- **एकीकृत शिक्षा** : कक्षा 1 से 12 तक की एकीकृत शिक्षा उपलब्ध करवाने में राज्य देश भर में प्रथम स्थान पर है।
- राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जहाँ विद्यार्थियों को सर्वाधिक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा एक ही स्थान पर उपलब्ध हो रही है।
- वर्ष 2024-25 में देश में केवल 5.4 प्रतिशत विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक एकीकृत शिक्षा मिल रही थी, वहीं राजस्थान में यह आँकड़ा पूरे देश का लगभग 35 प्रतिशत दर्ज किया गया।
- देश का 1 से 12वीं तक की एकीकृत शिक्षा उपलब्ध करवाने वाला हर तीसरा विद्यालय राजस्थान में संचालित है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (फ्लैगशिप योजना):

- **शुभारंभ** : 29 मार्च, 2025 (कोटा से)
- **पूर्ववर्ती नाम** : राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम।

--:6:--

Daily Current Affairs

Date : 13 May, 2026



- **नोडल विभाग :** स्कूल शिक्षा विभाग (राजस्थान सरकार)
- शिक्षा संबंधी इस तरह का व्यापक अभियान प्रारंभ करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।
- **उद्देश्य :** राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- **लक्ष्य :** नामांकन वृद्धि, सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार एवं विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास।
- **गतिविधियाँ :** अभियान के अंतर्गत 29 अप्रैल, 2025 से निम्नलिखित गतिविधियाँ प्रारंभ की गई हैं - AI आधारित मौखिक पठन प्रवाह (ORF) मूल्यांकन, छात्र उपस्थिति ऐप, NIOS हेतु ऑन डिमांड परीक्षाएँ (ODE) एवं डिजिटल पहलें।
- इस अभियान को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है।
अभियान के चार प्रमुख घटकों के तहत 41 कार्य:
 - (A) विद्यालय केंद्रित कार्य।
 - (B) विद्यार्थी केंद्रित कार्य।
 - (C) शिक्षक केंद्रित कार्य।
 - (D) शैक्षणिक परिणाम के उन्नयन केंद्रित कार्य।

--7--

मारवाड़ रत्न सम्मान - 2026

चर्चा में क्यों?

- जोधपुर के 568वें स्थापना दिवस के अवसर पर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा 'मारवाड़ रत्न सम्मान - 2026' प्रदान किए गए।

मुख्य बिन्दु:

- आयोजन स्थल : मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, जोधपुर।

प्राप्तकर्ता (19) :

क्रमांक	सम्मान का नाम	प्राप्तकर्ता
1.	वीर शिरोमणि सम्मान	परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह (मरणोपरान्त)
2.	राव सीहा सम्मान	डॉ. मांगी लाल जाट
3.	सर प्रताप सिंह सम्मान	एलन वेबर
4.	राव जोधा सम्मान	श्याम कुम्भट
5.	हनवंत सिंह सम्मान	डॉ. इशा दीक्षित व प्रणव दीक्षित
6.	मेजर दलपत सिंह सम्मान	विंग कमांडर दीपिका मिश्रा
7.	करणी सिंह जसोल सम्मान	मैमुना नरगिस जैदी
8.	कोमल कोठारी सम्मान	प्रो. जॉन डी स्मिथ
9.	विजयसिंह सम्मान	उमर मोहम्मद
10.	मानसिंह सम्मान	डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी
11.	उम्मेद सिंह सम्मान	डॉ. श्यामसुंदर पालीवाल

Daily Current Affairs

Date : 13 May, 2026



12.	बदन कंवर भटियाणी सम्मान	सरिता राठौड़
13.	कृष्णाकुमारी सम्मान	मोहनसिंह राठौड़
14.	गजसिंह-II सम्मान	झीमा देवी
15.	शिवराज सिंह सम्मान	संदीपसिंह मान
16.	राजाराम मेघवाल सम्मान	रफीक खान
17.	मोहता नैणसी सम्मान	डॉ. भुवनेश जैन
18.	सीताराम लालस सम्मान	नागराज शर्मा
19.	नारायण सिंह भाटी सम्मान	डॉ. मंगत बादल

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- सूर्यनगरी के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर शहर (मेहरानगढ़ दुर्ग) की स्थापना मारवाड़ के राठौड़ शासक राव जोधा ने 12 मई, 1459 को की थी।

--9--



'सुरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन' का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

चर्चा में क्यों?

- 'सुरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन' की 660-660 मेगावाट (कुल 1320 मेगावाट) की सातवीं और आठवीं इकाइयों ने वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च, 2026) में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।



मुख्य बिन्दु:

- वित्तीय वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही के दौरान दोनों सुपरक्रिटिकल इकाइयों ने रिकॉर्ड 95 प्रतिशत से अधिक के औसत प्लांट लोड फैक्टर पर काम किया।

--:10:--

Daily Current Affairs

Date : 13 May, 2026



- 'सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन' राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। वर्तमान में यह राजस्थान में सबसे अधिक बिजली उत्पादन करने वाला पावर प्लांट है।
- **स्वामित्व और संचालन** : राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) द्वारा।
- **स्थापना** : 1998, ठुकराना गाँव, सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)
- इस पावर प्लांट में 250 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाली 6 इकाइयाँ और 660 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाली 2 इकाइयाँ हैं। (250x6, 660x2)
- **कुल क्षमता** : 2820 MW
- 'सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन' में सुपरक्रिटिकल तकनीक पर आधारित 2x660 मेगावाट क्षमता की इकाई 7 एवं 8 से वाणिज्यिक उत्पादन क्रमशः 01 दिसंबर, 2020 एवं 07 अक्टूबर, 2021 को प्रारंभ हुआ था।

-:11:-

केंद्र सरकार की RCDF को ₹1500 करोड़ की सहायता हेतु सैद्धान्तिक सहमति

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने राजस्थान के डेयरी क्षेत्र का विस्तार करने और 'सरस' ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) को ₹1500 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने की सैद्धान्तिक सहमति दी।



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

RCDF
स्वाद... राजस्थान का!

केंद्र सरकार की
RCDF
(राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड)
को **₹1500 करोड़** की
सहायता हेतु सैद्धान्तिक सहमति

राजस्थान के दुग्ध विकास और
डेयरी उद्योग को मिलेगा नया बल

दुग्ध उत्पादन
को बढ़ावा

किसानों की आय
में वृद्धि

डेयरी उद्योग का
समग्र विकास

--:12:--



मुख्य बिन्दु:

- केंद्र सरकार द्वारा यह सहायता 2 अलग - अलग परियोजनाओं के तहत दी जाएगी।
- **परियोजना I** : जापान इन्टरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेन्सी (JICA) परियोजना के अंतर्गत ₹1000 करोड़ का फंड।
- **परियोजना II** : नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डवलपमेंट (NPDD) के तहत ₹500 करोड़ की सहायता।
- केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली इस राशि से RCDF द्वारा वर्तमान में प्रतिदिन संकलित किए जा रहे 45 लाख लीटर दूध को 65 लाख लीटर प्रतिदिन किया जा सकेगा।

राज्य में दुग्ध उत्पादन :

- **राज्य में दुग्ध संकलन (वर्ष 2025-26 में)** : लगभग 45 लाख लीटर प्रतिदिन।
- **दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता** : विगत 2 वर्ष में 51 लाख लीटर से बढ़कर 54 लाख लीटर प्रतिदिन।
- डेयरी के मार्केटिंग नेटवर्क में व्यापक विस्तार से दुग्ध उत्पादों के विपणन में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नए 'सरस' बूथ स्थापित किए जाने के साथ ही अन्य राज्यों में प्रतिदिन 1 लाख लीटर से अधिक दूध की आपूर्ति की जा रही है।
- सरस द्वारा भारतीय सेना को प्रतिवर्ष ₹250 करोड़ से अधिक के दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- पशुपालन और डेयरी विभाग की 'बेसिक एनीमल हस्बैंडरी स्टैटिस्टिक्स (BAHS) 2025' रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाद सम्पूर्ण देश में दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
- **शीर्ष - 5 दुग्ध उत्पादक राज्य** : उत्तर प्रदेश (15.66 प्रतिशत), राजस्थान (14.82 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (9.12 प्रतिशत), गुजरात (7.78 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (6.71 प्रतिशत)। ये सभी राज्य मिलकर देश के कुल दूध उत्पादन में 54.09 प्रतिशत का योगदान करते हैं।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स :

राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF)


- **स्थापना** : 1977 में (राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम - 1965 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत)
- **उद्देश्य** : राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना।

लखवार परियोजना का राजस्थान के लिए महत्त्व

चर्चा में क्यों?

- उत्तराखंड में यमुना नदी पर ताजेवाला हैडवर्क्स के अपस्ट्रीम में निर्माणाधीन लखवार बाँध परियोजना एक राष्ट्रीय बहुउद्देशीय परियोजना है, जो राजस्थान के पेयजल और सिंचाई संकट को दूर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

जल संसाधन मंत्री ने उत्तराखंड में निर्माणाधीन लखवार बांध का निरीक्षण किया



- यमुना जल समझौते के अंतर्गत, प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा कर, आवश्यक निर्देश दिए
- बांधों के निर्माण के लिए, राज्य सरकार ने अपनी हिस्सेदारी के 162 करोड़ रुपये दिए
- यमुना से शेखावाटी तक जल लाने के लिए, बजट में 32 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान
- यमुना जल शेखावाटी अंचल में लाने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार

-जल संसाधन मंत्री

RajGovOfficial



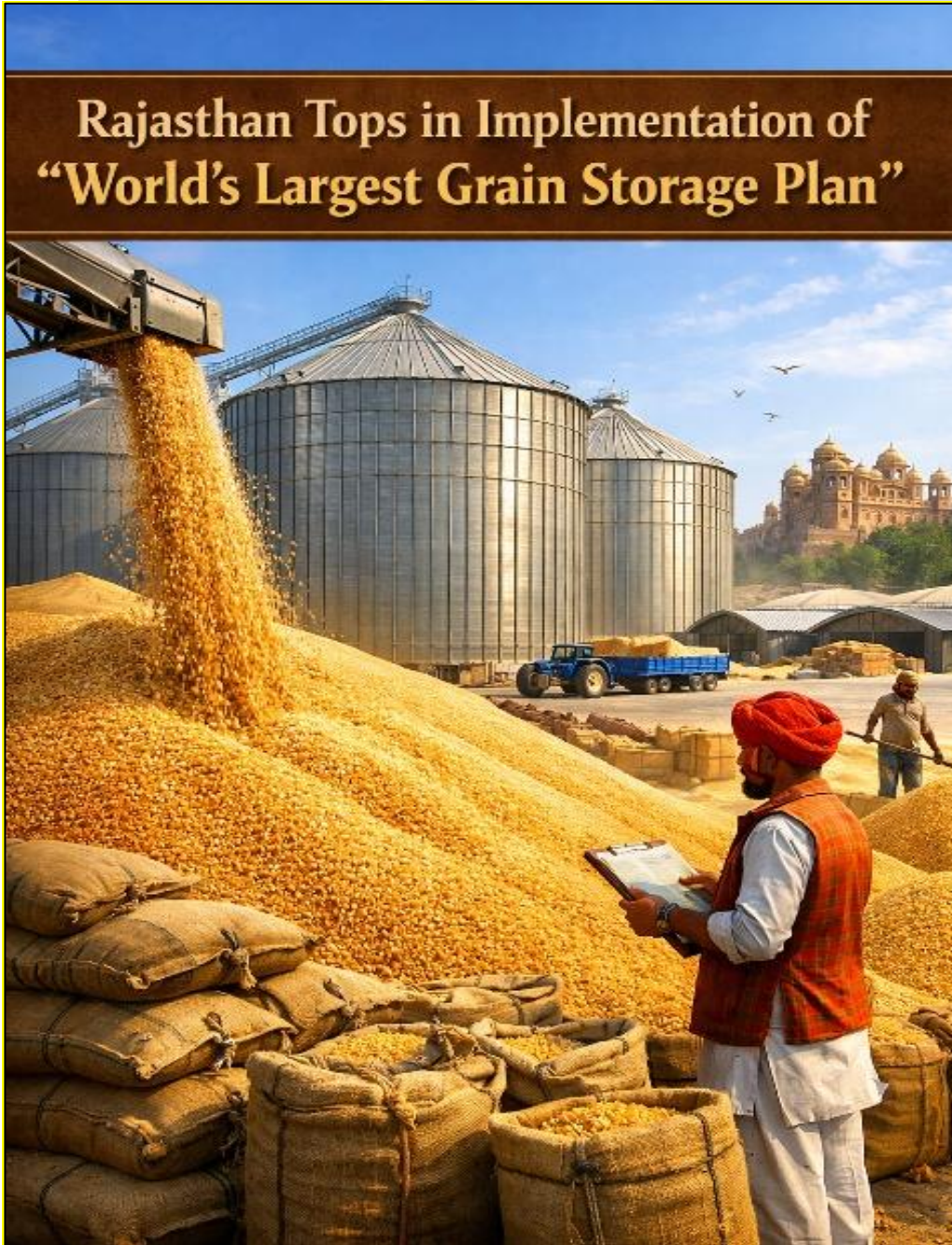
मुख्य बिन्दु:

- परियोजना की कुल भंडारण क्षमता : 331 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM)
- राजस्थान की हिस्सेदारी : लगभग 30.91 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM)
- परियोजना के संचालन से यमुना बेसिन में जल संरक्षण क्षमता बढ़ेगी तथा राजस्थान को पेयजल एवं सिंचाई के लिए स्थायी जल उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
- परियोजना के जल घटक पर केंद्र सरकार द्वारा 90 प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
- वर्ष 1994 के यमुना जल समझौते के अंतर्गत राजस्थान को यमुना नदी के जल में 9.338 प्रतिशत हिस्सेदारी आवंटित की गई।
- इसी समझौते के तहत यमुना बेसिन में जल के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से रेणुका, लखवार एवं किसान जैसी भंडारण परियोजनाओं की परिकल्पना की गई थी।

'विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना' के क्रियान्वयन में राजस्थान शीर्ष पर

चर्चा में क्यों?

- 'सहकार से समृद्धि' अभियान के अंतर्गत संचालित सहकारिता क्षेत्र में 'विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना' के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है।



-:16:-



मुख्य बिन्दु:

- भण्डारण निर्माण के राजस्थान मॉडल का अध्ययन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के एक दल ने हाल ही में राजस्थान का दौरा किया।
- राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है, जहाँ 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
- राज्य में 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले कुल 250 गोदामों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 100, वर्ष 2025-26 में 100 तथा वर्ष 2026-27 में 50 गोदामों का निर्माण लक्षित है। इससे राज्य में कुल 1.25 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का सृजन होगा।

योजना के बारे में:

- देश में अन्न भंडारण क्षमता की कमी को दूर करने के लिए 31 मई, 2023 को 'सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना' को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया जिसे प्रारंभ में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था।
- इस योजना में कृषि अवसंरचना निधि (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपयोजना (SMAM), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) आदि को एकीकृत किया गया है।
- योजना के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS) स्तर पर गोदामों, कस्टम हाइरिंग केंद्रों, प्रसंस्करण इकाइयों, उचित मूल्य की दुकानों जैसी विभिन्न कृषि अवसंरचना का निर्माण करना शामिल है।

प्री-एम्बेडेड मिनरल ब्लॉकों की नीलामी वाला देश का एकमात्र राज्य : राजस्थान

📢 चर्चा में क्यों?

- वित्त वर्ष 2025-26 में राजस्थान खान विभाग द्वारा 8 प्री-एम्बेडेड मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की गई। इसी के साथ राजस्थान प्री-एम्बेडेड मिनरल ब्लॉकों की नीलामी करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है।

📌 मुख्य बिन्दु:

- **प्री-एम्बेडेड नीलामी** : मिनरल ब्लॉकों की नीलामी से पहले ही आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त कर ब्लॉक की नीलामी करने की प्रक्रिया को 'प्री-एम्बेडेड क्लियरेन्स' कहा जाता है।
- **वित्त वर्ष 2026-27 का लक्ष्य** : मेजर मिनरल के 10 ब्लॉकों और करीब 100 माइनर मिनरल प्लॉट।
- **खान विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व संग्रहण का लक्ष्य** : विगत वित्त वर्ष की तुलना में 39 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ ₹14001 करोड़ है।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

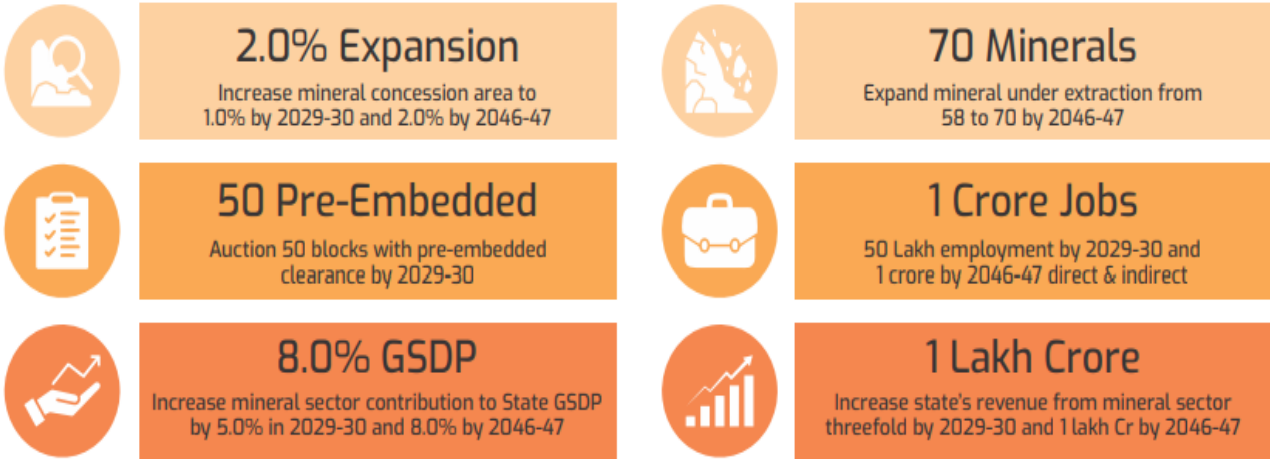
- **मिनरल व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम** : राजस्थान खनन विभाग द्वारा पूरे राज्य में 1 जनवरी, 2026 से 'मिनरल व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम' अनिवार्य किया जा चुका है।
- **ई-रवन्ना** : ई-रवन्ना एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली (एप) है, जिसे राजस्थान सरकार ने खनिज परिवहन में पारदर्शिता लाने, रॉयल्टी चोरी को रोकने और ओवरलोडिंग की समस्या से निपटने के लिए शुरू किया है। 31 अक्टूबर, 2017 के बाद से, बजरी और जिप्सम के लिए विशेष मामलों को छोड़कर, सभी प्रकार के खनिज परिवहन के लिए मैनुअल (भौतिक) रवन्ना जारी करना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स (आर्थिक समीक्षा - 2025-26)

राजस्थान में खनिज क्षेत्र:

- राजस्थान खनिज संसाधनों के सन्दर्भ में भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है, यहाँ 81 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं, जिनमें से 58 खनिजों का खनन किया जाता है।
- राजस्थान सीसा एवं जस्ता अयस्क, सेलेनाइट और वोलास्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है, वहीं चाँदी, कैल्साइट एवं जिप्सम के उत्पादन में देश में अग्रणी है।
- राजस्थान बॉल क्ले, फॉस्फोराइट, गेरू, स्टीटाइट, फेल्सपार और फायर क्ले के राष्ट्रीय उत्पादन में शीर्ष पर है।
- राजस्थान संगमरमर, बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट जैसे आयाती पत्थरों के साथ-साथ सीमेंट-ग्रेड और स्टील-ग्रेड चूना पत्थर का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है।

राजस्थान खनिज नीति - 2024



- जारी - 04 दिसंबर, 2024 को।
- राजस्थान खनिज नीति - 2024 का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास के लिए राज्य के प्रचुर खनिज संसाधनों का लाभ उठाते हुए टिकाऊ, पारदर्शी और जिम्मेदार खनिज विकास को बढ़ावा देना है।

Daily Current Affairs

Date : 13 May, 2026



मुख्य विशेषताएं:

- **आर्थिक विकास और निवेश:** खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में इस क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना।
- **रोजगार सृजन:** वर्ष 2047 तक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- **स्थिरता और ई.एस.जी. अनुपालन:** शून्य अपशिष्ट खनन, पर्यावरण अनुकूल तकनीकों और अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** उन्नत अन्वेषण तकनीकों, AI आधारित निगरानी और डिजिटल प्रशासन अपनाकर पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- **अवैध खनन शमन:** GPS- आधारित ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग और रीयल-टाइम निगरानी का उपयोग कर अवैध गतिविधियों को रोकना।

प्रमुख पहल :

- वर्ष 2047 तक खनिज निष्कर्षण को 58 से बढ़ाकर 70 तक करना।
- पूर्व-निर्धारित स्वीकृति के साथ 50 प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी।
- खनन रियायत क्षेत्र को वर्ष 2047 तक राज्य की कुल भूमि के 2 प्रतिशत तक बढ़ाना।
- स्वच्छ ऊर्जा के समर्थन में रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों (जैसे - लिथियम, दुर्लभ पृथ्वी तत्व) को बढ़ावा देना।
- खनिज संसाधनों में मूल्य संवर्धन और अनुसंधान हेतु एक राज्य खनन कंपनी की स्थापना करना।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (RSMET)

- **गठन :** वर्ष 2020 में।
- **उद्देश्य :** राजस्थान में उपलब्ध खनिज भण्डारों की वैज्ञानिक तरीके से खोज व खनन में आधुनिक तकनीक का उपयोग, अनुसंधान, शोध, कौशल विकास व राजस्व बढ़ोतरी सहित इससे जुड़ी गतिविधियों का बेहतर संचालन और मोनिटरिंग करना।

--:20:--



राष्ट्रीय परिदृश्य



राष्ट्रीय फ्लोरेस नाइटिंगेल पुरस्कार, 2026



चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रपति ने 12 मई, 2026 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस (वर्ष 2026 की थीम: "हमारी नर्सें, हमारा भविष्य") के अवसर पर, राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में देश भर के 15 उत्कृष्ट नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेस नाइटिंगेल पुरस्कार, 2026 प्रदान किए।



मुख्य बिन्दु:

- **स्थापना:** राष्ट्रीय फ्लोरेस नाइटिंगेल पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1973 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समाज को नर्सिंग कर्मियों द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं की मान्यता के प्रतीक के रूप में की गई थी।
- **पुरस्कार:** प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार और एक पदक शामिल है जो इन स्वास्थ्य योद्धाओं द्वारा प्रदान की गई अमूल्य सेवा के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है।

Daily Current Affairs

Date : 13 May, 2026



■ राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, 2026 के विजेता:

विजेता	संबंध
कुलविंदर परही	लद्दाख
उज्ज्वला महादेव सोयम	महाराष्ट्र
लालेनथांगी नामटे	मिजोरम
मधु माला गुरुंग	सिक्किम
पूजा परमार राणा	उत्तराखंड
गीता कर्माकर	पश्चिम बंगाल
पूनम वर्मा	चंडीगढ़
दीपा बीजू	दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव
श्रवण कुमार ढाका	दिल्ली
रक्षा रूपो पर्वतकर	गोवा
कविता जगन्नाथ	कर्नाटक
मंजू मोल वी एस	केरलम
आयशा बीबी के	लक्षद्वीप
आर शंकर शानमुगम	तमिलनाडु
मेजर जनरल लिसम्मा पी वी	IHQ, रक्षा मंत्रालय (सेना), दिल्ली

-:22:-

प्रशांत पिसे



चर्चा में क्यों?

- विदेश मंत्रालय में अपर सचिव प्रशांत पिसे को ओमान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है।



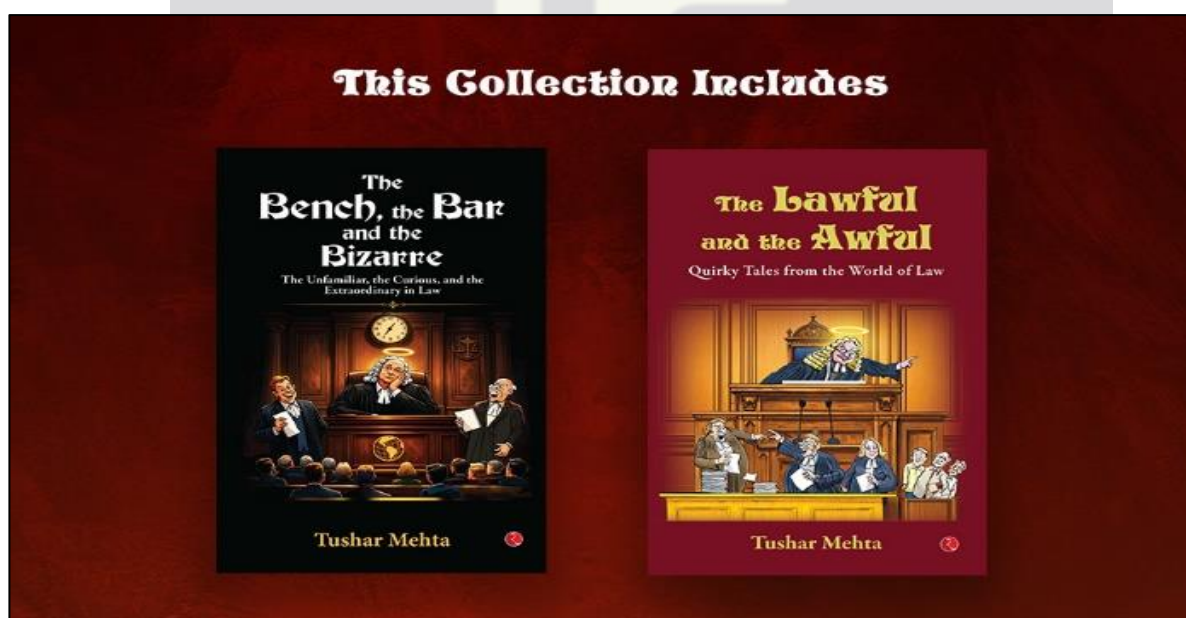
मुख्य बिन्दु:

- वर्ष 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी श्री पिसे मस्कट में, वर्ष 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी गोदावर्धी वेंकट श्रीनिवास का स्थान लेंगे।
- पिसे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में प्रवासी नीति और कल्याण विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत हैं।
- उन्होंने फरवरी, 2026 में दुबई में आयोजित अबूधाबी संवाद के आठवें मंत्री स्तरीय परामर्श के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

The Bench, the Bar, and the Bizarre और The Lawful and the Awful पुस्तक

चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता की किताबें The Bench, the Bar, and the Bizarre और The Lawful and the Awful का विमोचन किया।



मुख्य बिन्दु:

- लेखक:** यह दोनों पुस्तकें भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता द्वारा लिखी गई हैं।

- प्रकाशक:** रूपा पब्लिकेशंस।

पुस्तकों की विषय-वस्तु:

- The Bench, the Bar, and the Bizarre:** इस पुस्तक में दुनिया भर की अदालतों से जुड़े सनकी न्यायाधीशों, अजीबोगरीब कानूनी मामलों, वकीलों की अनूठी वाकपटुता और अदालत के भीतर होने वाले व्यंग्यपूर्ण और हास्यास्पद वाक्यों का संग्रह है।
- The Lawful and the Awful:** यह पुस्तक कानून की दुनिया के उन पलों को सामने लाती है जहां कानून की गंभीरता अचानक अप्रत्याशित और अजीब घटनाओं में बदल गई।

तीरंदाजी विश्व कप, 2026- चरण 2

चर्चा में क्यों?

- शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप- चरण 2 के फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को पांच-चार से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है।



मुख्य बिन्दु:

- आयोजन: 5 से 10 मई, 2026 तक शंघाई (चीन) में आयोजित किया गया।
- मेजबानी: चीन
- स्वर्ण पदक: भारत
- भारतीय महिला रिकर्व टीम: रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोद शामिल थीं।
- इससे पहले सेमीफाइनल में भारत ने दस बार के ओलम्पिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया था।

भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

असम और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, असम और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में क्रमशः सी. जोसेफ विजय और हिमंता बिस्व सरमा ने शपथ ग्रहण की।

मुख्य बिन्दु:

- संवैधानिक प्रावधान:** भारत के संविधान के अनुच्छेद-164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।
- तीसरी अनुसूची:** संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है।

तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री; सी. जोसेफ विजय:

- शपथ ग्रहण समारोह:** जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, तमिलनाडु
- राज्यपाल:** राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर
- तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) की जीत को राज्य में DMK-AIADMK की दशकों पुरानी द्विध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्था के अंत के रूप में देखा जा रहा है।



--:26:--

Daily Current Affairs

Date : 13 May, 2026



- **मुख्यमंत्री:** विजय DMK-AIADMK ढाँचे से बाहर रहकर तमिलनाडु में पदभार ग्रहण करने वाले दशकों में पहले नेता बने।

असम के नए मुख्यमंत्री; हिमंता बिस्व सरमा:

- **शपथ ग्रहण समारोह:** पशु चिकित्सा महाविद्यालय मैदान, गुवाहाटी

- **राज्यपाल:** लक्ष्मण प्रसाद आचार्य

- **मुख्यमंत्री:** भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।



- असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन-NDA ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटें हासिल की है।
- भारतीय जनता पार्टी 82 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है जबकि उसके सहयोगी दल - असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने 10-10 सीटें जीतीं।

-:27:-

'वन केस वन डेटा' और 'सु सहाय' पहल

चर्चा में क्यों?

- भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 11 मई, 2026 को सुप्रीम कोर्ट में “वन केस, वन डेटा” पहल और एआई आधारित चैटबॉट “सु सहायक” लॉन्च किया।

The infographic features a central image of the Supreme Court of India. To the left, three key points are listed: 'One Case One Data' (integrating judicial data across all levels), 'Seamless Access' (complete case details available), and 'Data Integrity & Transparency' (automated data retrieval). To the right, the 'Su-Sahayak' AI chatbot is introduced as a virtual assistant for case information and court services, with icons for case-related information, court services guidance, and help for litigants and lawyers. A quote from Chief Justice of India Surya Kant is at the bottom: "These initiatives will strengthen our justice delivery system and benefit all stakeholders." The infographic is developed by the National Informatics Centre in collaboration with the Supreme Court Registry.

मुख्य बिन्दु:

- सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है जो न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति न्यायालयों में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करेगी।

“वन केस, वन डेटा” पहल:

- परिचय: “वन केस, वन डेटा” एक डिजिटल डेटा इंटीग्रेशन प्रणाली है, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला अदालतों और तालुका अदालतों के केस रिकॉर्ड को एक मंच पर जोड़ा जाएगा।

Daily Current Affairs

Date : 13 May, 2026



- **उद्देश्य:** तालुका न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक, न्यायालयों के हर स्तर पर न्यायिक प्रशासन को एक एकीकृत प्रणाली में एकीकृत करना।
- **महत्त्व:** नई व्यवस्था के तहत हाई कोर्ट और सरकारी विभाग आवश्यकतानुसार एक-दूसरे के केस डेटा तक पहुँच प्राप्त कर सकेंगे। इससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, डेटा की शुद्धता और रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

एआई आधारित चैटबॉट "सु सहायक":

- **परिचय:** "सु सहायक" एक एआई आधारित चैटबॉट है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सहयोग से विकसित किया है।
- यह चैटबॉट सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट से जुड़ा हुआ है और नागरिकों को अदालत संबंधी जानकारी तथा सेवाओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
- **महत्त्व:** इस चैटबॉट की सहायता से लोग केस की जानकारी, फाइलिंग प्रक्रिया और अन्य न्यायिक सेवाओं से जुड़ी प्रारंभिक जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति:

- **अध्यक्ष:** न्यायमूर्ति अरविंद कुमार
- **सदस्य:** कलकत्ता, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तथा बॉम्बे उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक, अश्वनी कुमार मिश्रा और सोमशेखर सुंदरेशन शामिल होंगे तथा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के महानिदेशक और सुप्रीम कोर्ट के महासचिव भी समिति के सदस्य होंगे।
- समिति 31 अगस्त, 2026 तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

- **मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत:** न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने नवंबर, 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला था। उनका कार्यकाल फरवरी, 2027 तक निर्धारित है। उनके नेतृत्व में न्यायपालिका में तकनीक आधारित सुधारों पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

--:29:--

न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी:

- **शुरुआत:** भारत में, न्याय प्रशासन के क्षेत्र में ई-गवर्नेंस की शुरुआत वर्ष 1990 के दशक के उत्तरार्ध में हुई, लेकिन सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के लागू होने के बाद इसमें तेजी आई।
- वर्ष 2006 में, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NEGP) के एक भाग के रूप में ई-अदालतों की शुरुआत की गई थी।
- 1. **कृष्णा वेनी नागम बनाम हरीश नागम (वर्ष 2017):** सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैवाहिक मामलों की सुनवाई को मंजूरी दी थी। हालाँकि, यह निर्देश अल्पकालिक था।
- 2. **इलाहाबाद उच्च न्यायालय:** इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने एक वर्ष में लगभग एक करोड़ केस फाइलों को डिजिटाइज़ करने की परियोजना की परिकल्पना की और उसे शुरू किया।
- 3. **स्वप्निल त्रिपाठी बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 2018:** सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों की लाइव-स्ट्रीमिंग की अनुमति दी थी।
- 4. **गुजरात उच्च न्यायालय:** जुलाई, 2021 में गुजरात उच्च न्यायालय देश का पहला न्यायालय बन गया, जिसने अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया तथा कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश और पटना की उच्च न्यायालय ने भी इसका अनुकरण किया।
- 5. **ई-कोर्ट परियोजना:** न्यायपालिका की डिजिटल सुविधाओं से वंचित होने की समस्या को दूर करने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के लिए नवीनतम विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया था।

योजनाएँ एवं नीतियाँ

सेहत मिशन (SEHAT)

चर्चा में क्यों?

- 11 मई, 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री ने दिल्ली में "सेहत मिशन" लॉन्च किया गया।



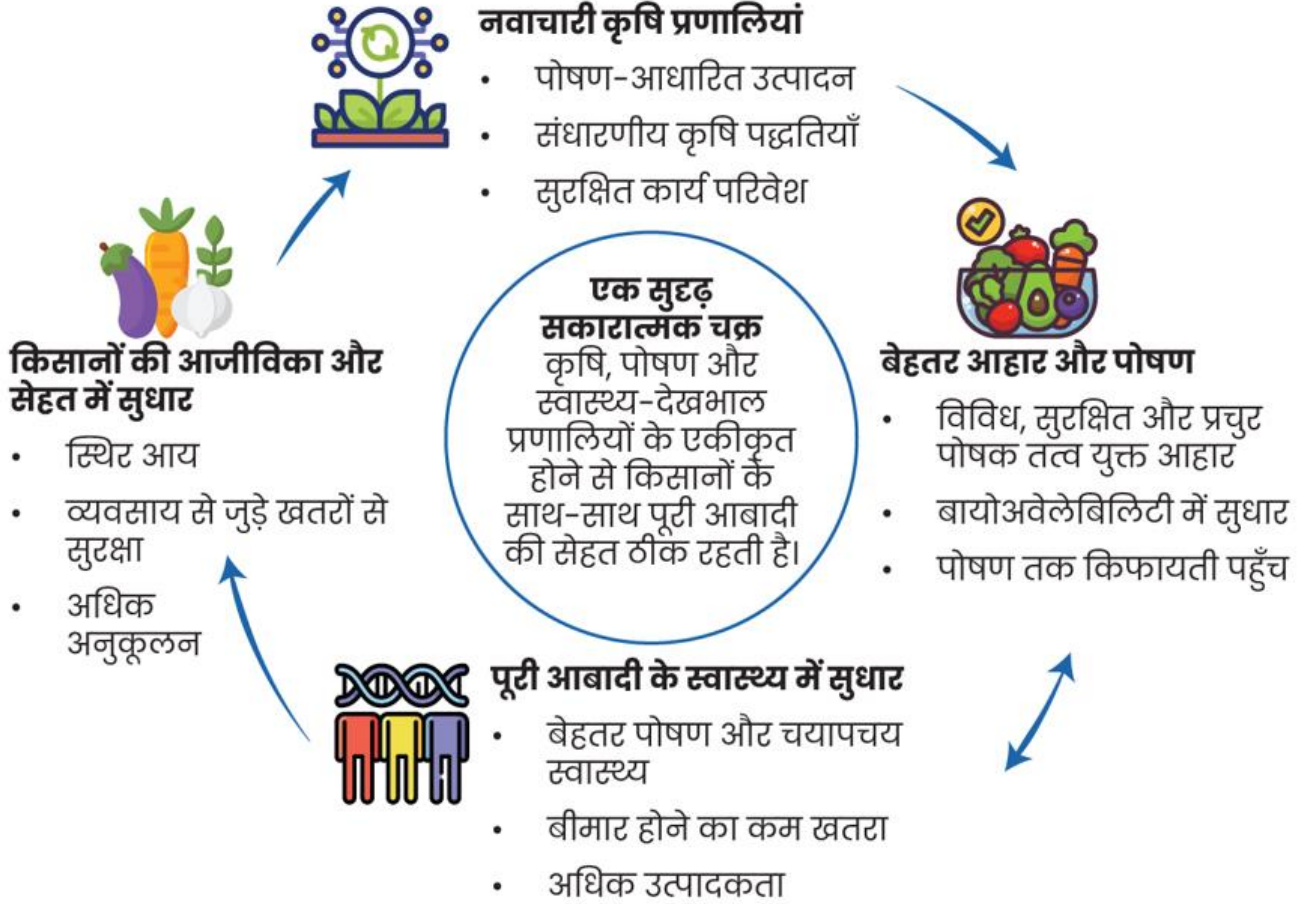
मुख्य बिन्दु:

- परिचय:** यह ICAR-ICMR की साझेदारी से प्रारंभ हेल्दी फूड, हेल्दी फार्म और हेल्दी इंडिया का नया महत्त्वपूर्ण मिशन है।

- **पूर्ण रूप:** SEHAT; Science Excellence for Health through Agricultural Transformation
- **शुरुआत:** ICAR और ICMR का संयुक्त राष्ट्रीय मिशन हैं।
- **उद्देश्य:** खेती को बेहतर पोषण, रोग-निवारण, किसान कल्याण और वैज्ञानिक नीति-निर्माण से जोड़ना।
- **अपेक्षित प्रभाव:** मिशन के अपेक्षित प्रभावों में पोषण गुणवत्ता में सुधार, छिपी भूख और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी में कमी, गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, किसान स्वास्थ्य-सुरक्षा, टिकाऊ खाद्य प्रणाली और विज्ञान-आधारित नीति समर्थन शामिल हैं।
- **मिशन की विशेषताएँ:**
 1. **गैर-संचारी रोगों (NCDs) की रोकथाम और प्रबंधन:** यह मिशन कुपोषण और दूसरी ओर तेजी से बढ़ रही नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर, दोनों चुनौतियों से निपटने में बड़ी भूमिका निभाएगा।
 2. **होल ऑफ सिस्टम्स अप्रोच:** सेहत मिशन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सिस्टम्स अप्रोच का उदाहरण है, जिसमें विज्ञान, नीति और क्रियान्वयन को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा।
 3. यह मिशन हेल्दी इंडिया और स्ट्रॉन्ग इंडिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
 4. **'वन हेल्थ' दृष्टिकोण:** यह मिशन बायो-फोर्टिफाइड फसलों, पोषणयुक्त खाद्य पदार्थों, एकीकृत कृषि प्रणाली, किसानों के स्वास्थ्य-सुरक्षा उपायों, जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के लिए उपयुक्त आहार और वन हेल्थ दृष्टिकोण पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए खाद्य फसलों को जिंक, आयरन (लौह) और अन्य पोषक तत्वों से समृद्ध करना।
 5. **एकीकृत कृषि प्रणाली:** फसल + फल + सब्जियाँ + पशुपालन + मत्स्य पालन + मधुमक्खी पालन।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

स्वस्थ रहने के लिए कृषि पर ध्यान देना क्यों आवश्यक है?



SERVICES

जन सुरक्षा योजना (PMJJBY, PMSBY और APY) : 11 वर्ष पूर्ण

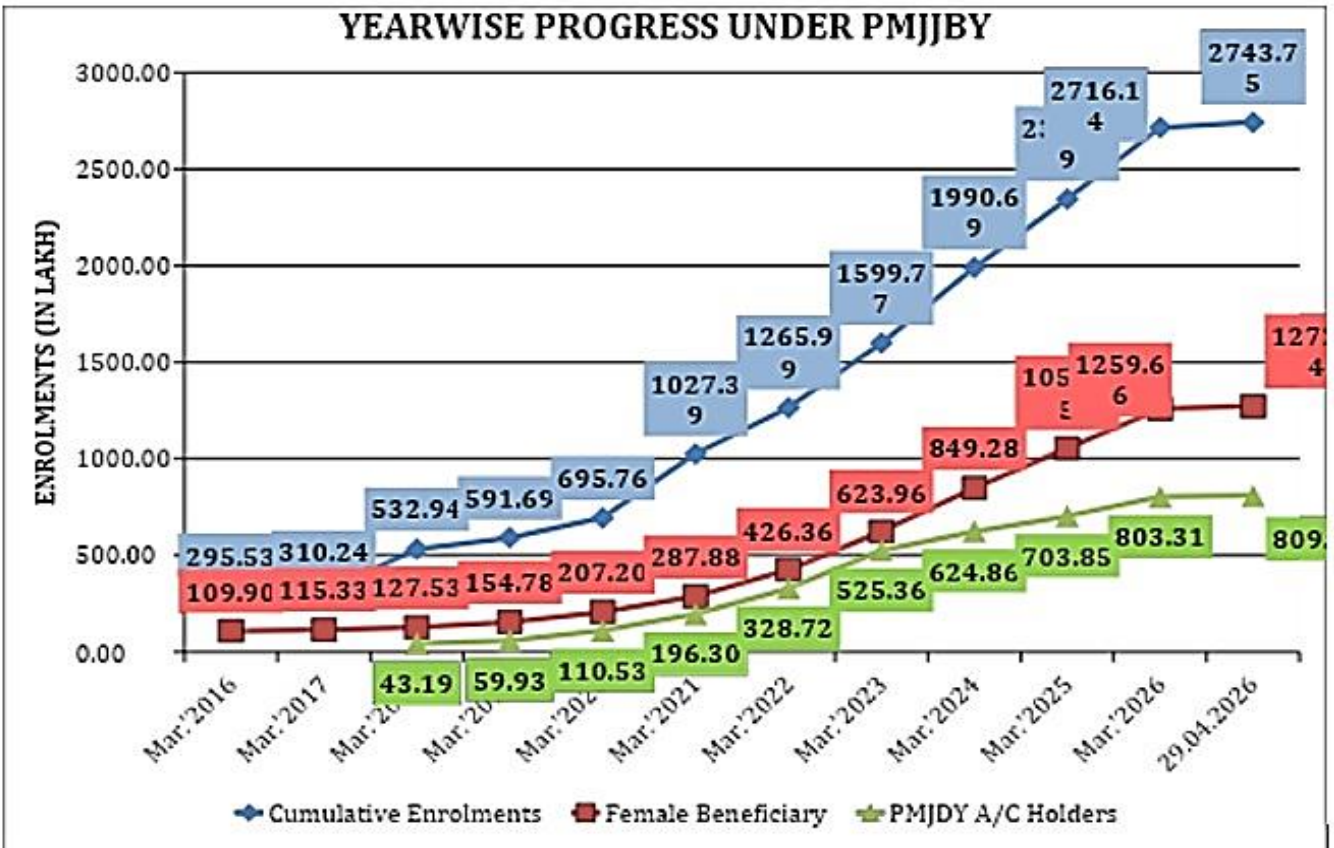
चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई, 2015 को शुरू की गई जनसुरक्षा योजनाएँ - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना (APY) - समाज के सभी वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

मुख्य बिन्दु:

- इन प्रमुख योजनाओं का लक्ष्य नागरिकों को जीवन की अनिश्चितताओं से बचाकर और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देकर बीमा और पेंशन व्यवस्था को व्यापक बनाना है।
- जन सुरक्षा योजनाओं की 11वीं वर्षगाँठ के आँकड़ों के अनुसार PMJJBY, PMSBY और APY के तहत क्रमशः 27 करोड़, 58 करोड़ और 9 करोड़ से अधिक नामांकन हुए हैं।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY):

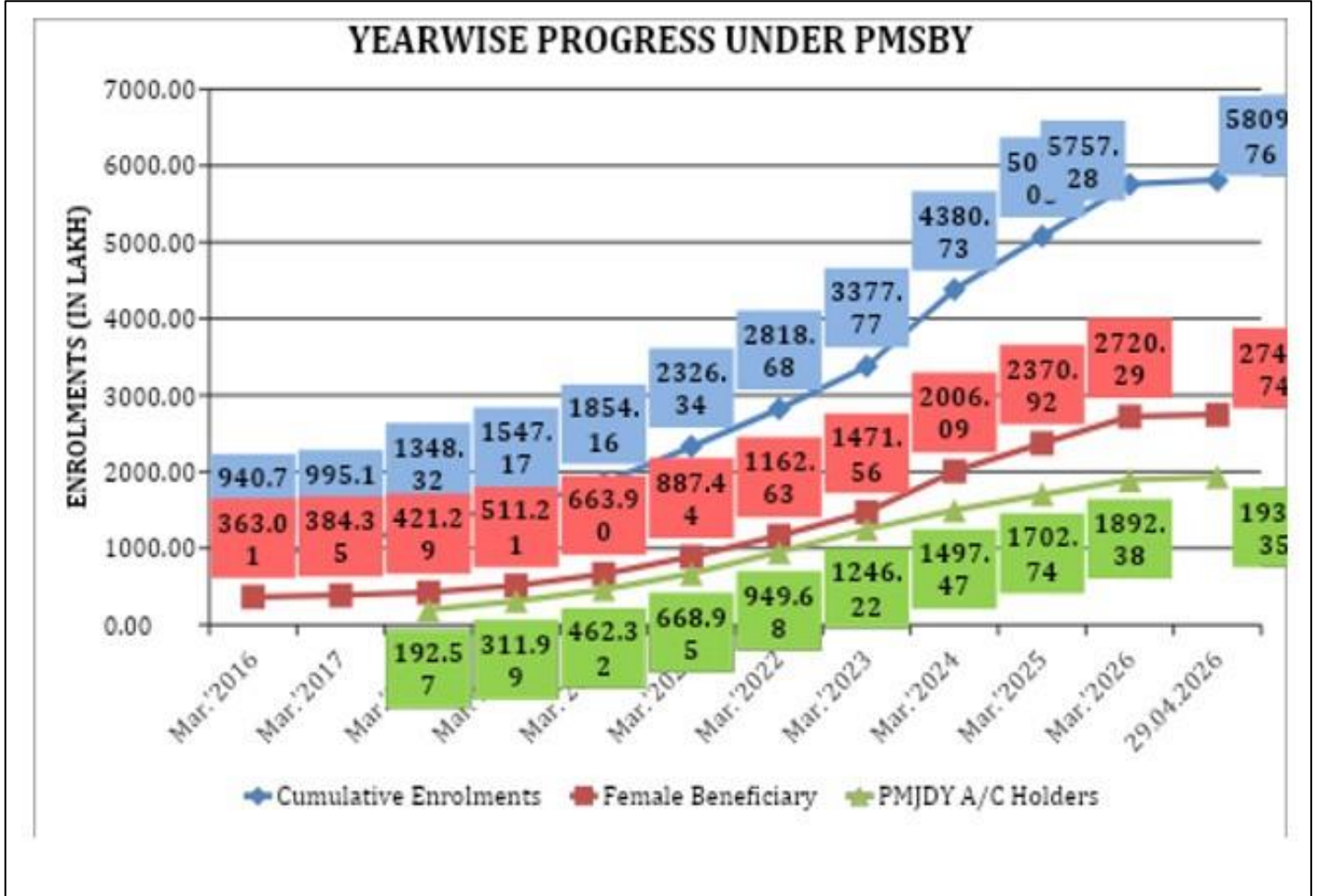


- **परिचय:** यह एक कम लागत वाली जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।

योजना की मुख्य विशेषता:

1. **अवधि:** पीएमजेजेबीवाई एक वर्षीय बीमा योजना है, जिसे हर साल नवीनीकृत किया जा सकता है।
 2. **संचालन:** यह योजना LIC और अन्य जीवन बीमा कंपनियों जो आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने और बैंकों/डाकघरों के साथ साझेदारी करने के बाद समान शर्तों पर यह उत्पाद प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं, द्वारा संचालित की जाती है।
 3. **जीवन बीमा कंपनी की नियुक्ति की स्वतंत्रता:** सहभागी बैंक/डाकघर अपने ग्राहकों के लिए योजना को लागू करने हेतु किसी भी जीवन बीमा कंपनी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- **पात्रता शर्तें:** योजना में भाग लेने वाले बैंकों/डाकघरों के 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के सभी व्यक्तिगत खाताधारक, जो ऑटो-डेबिट में शामिल होने/चालू करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं।
 - **प्रीमियम:** 436/- रुपये प्रति वर्ष प्रति सदस्य। योजना में नामांकन के समय दिए गए विकल्प के अनुसार, प्रीमियम खाताधारक के बैंक/डाकघर खाते से 'ऑटो डेबिट' सुविधा के माध्यम से एक ही किश्त में काट लिया जाएगा।
 - **लाभ:** ग्राहक की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। नामांकन की तिथि से 30 दिनों की ग्रहणाधिकार अवधि लागू होगी।
 - **उपलब्धियाँ:** 29 अप्रैल, 2026 तक, PMJJBY के तहत कुल नामांकन 27.43 करोड़ से अधिक हो चुके हैं और 10,75,625 दावों के लिए 21,512.50 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):



- परिचय:** प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) को दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता होने पर 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को 2 लाख रुपये तक का आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसका न्यूनतम प्रीमियम 2 रुपये प्रति माह से कम है।
- पात्रता शर्तें:** योजना में भाग लेने वाले बैंकों/डाकघरों के 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के सभी व्यक्तिगत खाताधारक, जो ऑटो-डेबिट में शामिल होने/चालू करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं।
- प्रीमियम:** 20 रुपये प्रति वर्ष प्रति सदस्य। योजना में नामांकन के समय दिए गए विकल्प के अनुसार, प्रीमियम खाताधारक के बैंक/डाकघर खाते से 'ऑटो डेबिट' सुविधा के माध्यम से एक ही किस्त में काट लिया जाएगा।

Daily Current Affairs

Date : 13 May, 2026

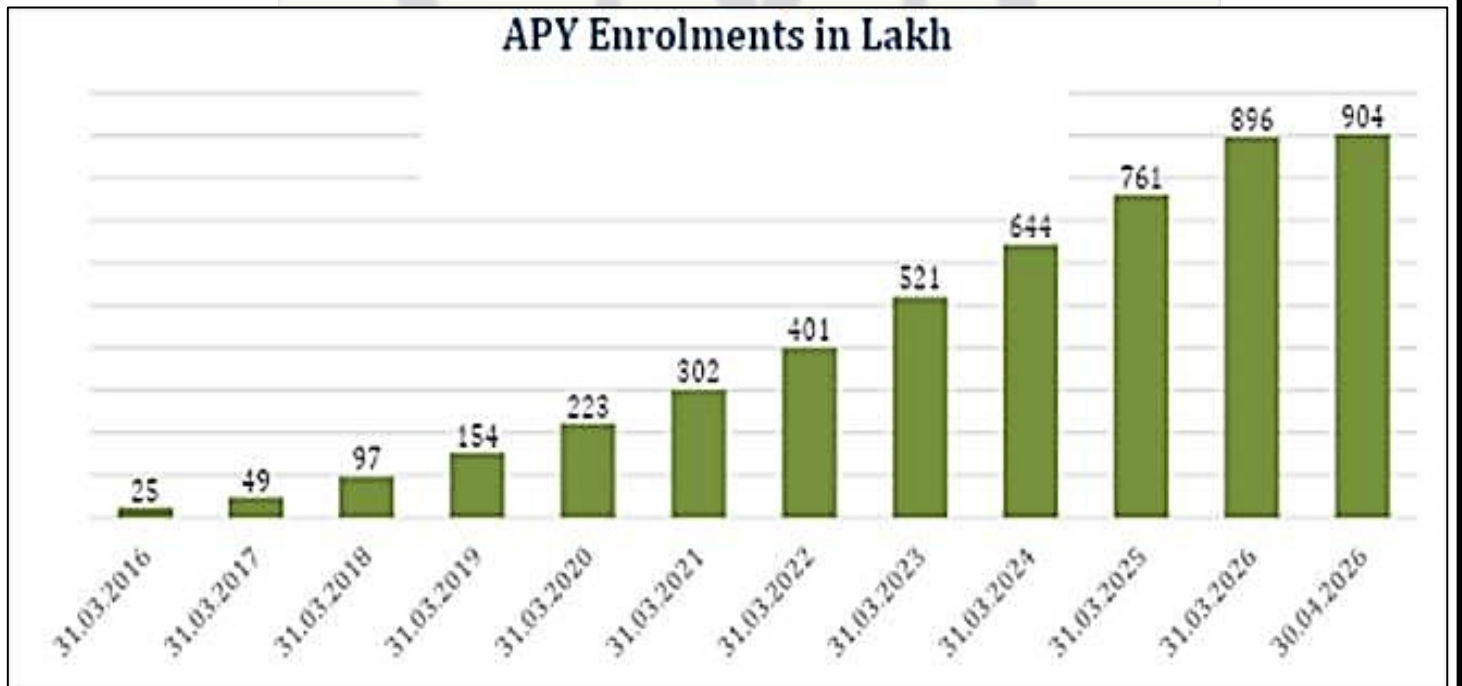


■ लाभ:

लाभ	बीमा - राशि
मृत्यु होने पर	2 लाख रुपये
दोनों आँखों की पूर्ण और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाना या एक आँख की रोशनी का नुकसान और एक हाथ या एक पैर की क्षति	2 लाख रुपये
एक आँख की दृष्टि का पूर्ण और अपूरणीय क्षति या एक हाथ या एक पैर की क्षति	1 लाख रुपये

- **उपलब्धियां:** 29 अप्रैल, 2026 तक, PMSBY के तहत कुल नामांकन 58.09 करोड़ से अधिक हो चुके हैं और 1,84,662 दावों के लिए 3,667.52 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

अटल पेंशन योजना (APY):



--:37:--

- **परिचय:** यह असंगठित क्षेत्र के लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और भविष्य की आपात स्थितियों से निपटने के लिए सरकार की एक पहल है।
- **उद्देश्य:** अटल पेंशन योजना का उद्देश्य सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- **संचालन:** APY का संचालन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की समग्र प्रशासनिक और संस्थागत संरचना के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जाता है।
- **पात्रता:** APY 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुला है जो आयकर दाता नहीं हैं और चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर अंशदान भिन्न होते हैं।
- **लाभ:** योजना में शामिल होने के बाद ग्राहक द्वारा किए गए अंशदान के आधार पर, ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये या 5000 रुपये की गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त होगी।
- **योजना के लाभों का वितरण:** मासिक पेंशन ग्राहक को उपलब्ध होती है, और उसके बाद उसके जीवनसाथी को, और उनकी मृत्यु के बाद, ग्राहक की 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि ग्राहक के नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।
- ग्राहक की असामयिक मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु) की स्थिति में, ग्राहक का जीवनसाथी शेष निहित अवधि के लिए ग्राहक के एपीवाई खाते में योगदान जारी रख सकता है, जब तक कि मूल ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।
- **भुगतान:** ग्राहक मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक आधार पर एपीवाई में योगदान कर सकते हैं।
- **योजना से निकासी:** ग्राहक कुछ शर्तों के अधीन, सरकारी सह-योगदान और उस पर प्राप्त लाभ/ब्याज की कटौती के बाद, स्वेच्छा से एपीवाई से बाहर निकल सकते हैं।
- **उपलब्धि:** इस योजना के अंतर्गत कुल नामांकनों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 49% है।

⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी ⚡

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 2026

📢 चर्चा में क्यों?

- 11 मई, 1998 को पोखरण परमाणु परीक्षणों की स्मृति में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन किया गया।



-:39:-



मुख्य बिन्दु:

- पहला राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस: 11 मई, 1999
- वर्ष 2026 की थीम/ विषय: "समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार,"
- राष्ट्रीय कार्यक्रम 'विज्ञान - टेक': भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 2026 के अवसर पर BRIC-राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान (NII), नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम 'विज्ञान - टेक' में भाग लिया।
- आयोजक: इसका मुख्य रूप से आयोजन प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक वैधानिक निकाय है।
- ICMR ने जैव-फार्मा, स्वास्थ्य और जैव-औद्योगिक एवं हरित रसायन क्षेत्रों में फैली छह उच्च-प्रभावशाली स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया। इनमें कोवैक्सिन, कोविड कवच एलिसा किट, CRISPR-कैस आधारित टीबी पहचान प्रणाली, निपाह प्वाइंट-ऑफ-केयर एसे, डेंगू की पहचान के लिए एक डायग्नोस्टिक एलिसा किट और मच्छर नियंत्रण के लिए एक बायोलाविंसाइड शामिल थे।
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 2026 के अवसर पर ICMR ने तीन स्वदेशी चिकित्सा प्रौद्योगिकियों को उद्योग को हस्तांतरित की।
 1. पहली तकनीक, जिसका शीर्षक "पीएसए 20 ng/ml से कम वाले मरीजों में प्रोस्टेट बायोप्सी के फ़ैसलों में मदद के लिए एक किफ़ायती PSP 94 एलिसा का विकास" है, को ICMR-नेशनल इंस्टीट्यूट फ़ॉर रिसर्च इन वीमेन्स हेल्थ (ICMR-NIRWOH) में डॉ. धनश्री जगताप, डॉ. स्मिता महाले और डॉ. भक्ति पाठक ने विकसित किया था। इस तकनीक का लाइसेंस कृषजेन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था।
 2. दूसरी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में "फैक्टर VIII इनहिबिटर / कोगुलेशन डिसऑर्डर पॉइंट-ऑफ-केयर डायग्नोस्टिक" शामिल था, जिसे ICMR-नेशनल इंस्टीट्यूट फ़ॉर रिसर्च ऑन ब्लड एंड इम्यून डिसऑर्डर्स (ICMR-NIRBID) में डॉ. रुचा पाटिल द्वारा विकसित किया गया था। इस प्रौद्योगिकी का लाइसेंस मेरिल लाइफ साइंसेज को दिया गया था।

3. तीसरी तकनीक, "डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस का पता लगाने के लिए सिंगल-ट्यूब मल्टीप्लेक्स रियल-टाइम RT-PCR," को ICMR-राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (ICMR-NIV) में डॉ. अलागारासु के द्वारा विकसित किया गया था और वैनगार्ड लाइफ साइंसेज को लाइसेंस दिया गया था।
- इस कार्यक्रम के दौरान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद- केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित 13 प्रौद्योगिकियों को विभिन्न उद्योगों और स्टार्टअप्स को औपचारिक रूप से हस्तांतरित किया गया। इन प्रौद्योगिकियों में अग्नि सुरक्षा, दीर्घकालिक निर्माण, अवसंरचना संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और उन्नत निर्माण सामग्री जैसे क्षेत्र शामिल थे।
 - **हस्तांतरित प्रमुख प्रौद्योगिकियों में शामिल हैं:**
 1. लकड़ी और लकड़ी के विकल्प से बनी सतहों के लिए अग्निरोधी पारदर्शी इंट्यूमेसेंट कोटिंग
 2. आरसीसी संरचनाओं की सुरक्षा के लिए आईपीएन कोटिंग तकनीक
 3. कम कार्बन फुटप्रिंट वाली ईट निर्माण तकनीक
 4. हाइब्रिड सौर-सहायता प्राप्त हीट पंप प्रणाली
 5. दीवार सुरक्षा के लिए पूर्वनिर्मित उच्च-शक्ति स्टील कॉर्ड सुदृढीकरण तकनीक
 - **ऑपरेशन शक्ति (पोखरन-II):**
 - भारत ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में वर्ष 1998 में पाँच परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था।
 - वर्ष 1998 में पोखरण-द्वितीय परमाणु परीक्षणों के बाद, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को परमाणु-सशस्त्र घोषित किया।
 - यह वर्ष 1974 में किए गए पोखरण-I (ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा) के बाद किया गया था।
 - उसी दिन, भारत ने त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया और स्वदेशी विमान हंसा-3 की परीक्षण उड़ान का संचालन किया

ICGS अचल

चर्चा में क्यों?

- भारतीय तटरक्षक बल ने 9 मई, 2026 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय तटरक्षक पोत (ICGS) अचल को सेवा में शामिल कर अपनी परिचालन क्षमता को और मजबूत किया है।



मुख्य बिन्दु:

- 'अचल' नाम का अर्थ: अडिग / दृढ़
- डिजाइन और निर्मित: मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा।
- श्रेणी: यह नई पीढ़ी की अदम्य-श्रेणी में तीव्र गति के जहाजों की श्रृंखला का नवीनतम पोत है।

विशेषताएँ

- 1. प्रणोदन:** यह दो 3000 किलोवाट के उन्नत डीजल इंजनों द्वारा संचालित है।
 - 2. गति:** यह पोत 27 समुद्री मील की अधिकतम गति और 1500 समुद्री मील की परिचालन सहनशक्ति प्रदान करता है।
 - 3.** इसमें एकीकृत ब्रिज सिस्टम, एकीकृत मशीनरी नियंत्रण प्रणाली और स्वचालित विद्युत प्रबंधन प्रणाली सहित एकीकृत प्रौद्योगिकियों का एक समूह शामिल है।
 - 4.** 50 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी घटकों से सुसज्जित यह जहाज रक्षा निर्माण क्षेत्र में देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है और इसे दोहरी श्रेणी का प्रमाणन (ABS और IRS) प्राप्त है।
- **कार्य:** यह अत्याधुनिक पोत समुद्री अभियानों की व्यापक जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम है, जिनमें तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज एवं बचाव (SAR), तस्करी-रोधी अभियान तथा समुद्री प्रदूषण से निपटने जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।

फुल स्केल एक्टिवली कूल्ड लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रेमजेट कंबस्टर/इंजन

चर्चा में क्यों?

- 9 मई, 2026 को DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला (DRDL) ने अपने सक्रिय रूप से कूल्ड फुल स्केल स्क्रेमजेट कंबस्टर का व्यापक और दीर्घकालिक परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न करके हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है।



मुख्य बिन्दु:

- **सफल परीक्षण:** इस वर्ष जनवरी में 700 सेकंड से अधिक समय तक चले एक सफल परीक्षण के बाद 9 मई, 2026 को हैदराबाद में अत्याधुनिक स्क्रेमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट (SCPT) सुविधा में 1200 सेकंड से अधिक समय तक चलने वाला एक सफल परीक्षण आयोजित किया गया।

--:44:--

Daily Current Affairs

Date : 13 May, 2026



- **डिजाइन और विकसित:** इस कंबस्टर को DRDO की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL), हैदराबाद द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और उद्योग भागीदारों द्वारा इसे साकार रूप दिया गया है।

तकनीकी विशेषताएँ:

1. **एक्टिव कूलिंग (सक्रिय शीतलन):** उच्च तापमान थर्मल बैरियर कोटिंग (TBC) और उन्नत विनिर्माण प्रक्रियाओं का उपयोग करके इंजन को अत्यधिक गर्मी (स्टील के गलनांक से अधिक) से बचाया गया।
 2. **स्वदेशी ईंधन:** यह उल्लेखनीय उपलब्धि अत्याधुनिक सुपरसोनिक एयर-ब्रीदिंग इंजन के माध्यम से हासिल की गई है, जो स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोकार्बन एंडोथर्मिक ईंधन (Liquid Hydrocarbon Endothermic Fuel) का उपयोग किया गया, जो ईंधन और शीतलक (Coolant) दोनों के रूप में कार्य करता है।
- **महत्त्व:** इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी।

--:45:--